भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3001
दिनांक 18 दिसंबर 2025

नये रिटेल आउटलेट

†3001. श्री अरुण भारतीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत एक वर्ष के दौरान जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा कमीशन किए गए नए रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल/डीजल पंप) की संख्या कितनी है;

(ख) जमुई-मुंगेर क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थिति क्या है और उसके कच्चे माल की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के समर्थन का ब्यौरा क्या है;

(ग) जमुई जिले में रिटेल आउटलेट्स पर ई-20 (बीस प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन) की बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) जमुई जिले में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सीएसआर गतिविधियों हेतु सीपीएसयू द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या बिहार में युवाओं हेतु पेट्रोलियम और गैस रिटेल क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) के नेटवर्क का विस्तार करके पूरे देश में पेट्रोल और डीजल जैसे मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, एक सतत प्रक्रिया है। आरओज की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा

क्षेत्रीय सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर अभिज्ञात स्थलों पर की जाती है। पर्याप्त क्षमता रखने वाले और आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थलों को आरओज की स्थापना करने के लिए विपणन योजनाओं में सूचीबद्ध किया जाता है। जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के जिले तक फैला हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने वर्ष 2024-25 के दौरान जमुई, मुंगेर और शेखपुरा जिलों में 9 खुदरा बिक्री केंद्र कमीशन किए हैं।

(ख) उद्यमी/कंपनियां/सहकारी समितियां आदि अपनी निवेश योजनाओं के अनुसार परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर ईथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने सूचित किया है कि जमुई क्षेत्र में मैसर्स अंकुर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक खाद्यान-आधारित डिस्टिलरी इकाई स्थापित की गई है। सरकार ने भारत में ईथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमत फीडस्टॉक की श्रेणी में विस्तार किया है।

(ग) वर्तमान में देश की मुख्य भूमि पर सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के सभी आरओज में ई-20 ईंधन वितरित किया जा रहा है, जिसमें जमुई जिला भी शामिल है, जहां पेट्रोल बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुख पहलें और बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों की देखभाल करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत अभिज्ञात शीर्षों के तहत नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप करती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने वर्ष 2025-26 के दौरान जमुई जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अभिनव स्कूल बैग परियोजना हेतु सीएसआर के तहत 198.86 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

(ङ) वर्तमान में, बिहार में पेट्रोलियम और गैस के खुदरा क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

*****